



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2009/आषाढ़ 17, 1931

No. 393]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2009/ASADHA 17, 1931

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 510(अ).—लोक शिकायत निवारण नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) अधिसूचना सं. 233(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 9 अप्रैल, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक शिकायत निवारण नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक शिकायत निवारण (.....संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक शिकायत निवारण नियम, 1998 के नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“9. आम्बड्समैन का वेतन और भत्ते.—(1) आम्बड्समैन को, प्रतिमास अस्सी हजार रुपये का नियत वेतन अनुज्ञात किया जाएगा और किसी पेंशन की, जिसके लिए वह केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संगठन या संस्था से हकदार है, उसके वेतन से कटौती की जाएगी।

(2) पुनरीक्षित वेतन और अन्य भत्तों तथा परिलब्धियों की स्वीकार्यता को लागू करने की प्रभावी तारीख वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए।”

[फा. सं. 56/32/2008-बीमा-I]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 670(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ती निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. 752(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 1998।

2. सा.का.नि. 448(अ), तारीख 21 जून, 1999।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2009

G.S.R. 510(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Redressal of Public Grievance Rules, 1998 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 2nd April, 2009 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division) number 233(E), dated the 2nd April, 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 9th April, 2009;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred sub-section (1), Section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Redressal of Public Grievance Rules, 1998, namely :—

1. (1) These rules may be called the Redressal of Public Grievances (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Redressal of Public Grievances Rules, 1998, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely :—

“9. Pay and Allowances of Ombudsman.— (1) The Ombudsman shall be allowed a fixed pay of eighty thousand rupees per month and any pension to which he is entitled from the Central Government or a State Government or any other organization or institution shall be deducted from his salary.

(2). The effective date for application of the revised pay and admissibility of other allowances and perquisites shall be such as may be determined by the Central Government”.

[F. No. 56/32/2008-Ins.-I]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal rules were published under notification No. G.S.R. 670(E), dated the 11th November, 1998 and subsequently amended *vide* :—

1. No. G.S.R. 752(E), dated the 18th December, 1998.

2. No. G.S.R. 448(E), dated the 21st June, 1999.